(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी की बुराइयों को रोकने के लिए बनाए गए दो मुख्य कानून है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों को लागू कर रहे हैं। उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई हैं कि वे इन अधिनियमों को जोरदार ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाएं।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1990 के दौरान 30-7-1990 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 2718 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1921 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। 13 सप्ताह (28-4-90 से 28-7-90 तक) की अवधि के दौरान यद्यपि खाद्य तेलों, चावल, गेहूं, चना तथा अरहर के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया, तथापि, चाय, चीनी, आटा, मैदा, काली मिर्च तथा लाल मिर्च जैसी मदों के सूचकांकों में गिरावट का रुख दिखाई दिया।

Refusal for Registration by Employment Exchange, R. K. Puram

1179. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, as reported by UNI in its despatches of July 4, 1990, that the Regional Employment Exchange Office at R. K. Puram in South Delhi had refused registration to hundreds of job seekers holding B.A. mark sheet certificates;

(b) what was the number of such job seekers who were declined registration; and

(c) what steps are being taken by Government to save unemployed youth from such harassment in the future?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) According to information received from Delhi Administration, no such candidate has been refused registration. To exercise a check on undue refusal, a system of issuing refusal slips indicating reasons for refusal has been introduced at employment exchanges. While the timings of registration have been increased to cope with rush of work instructions have also been issued to open additional registration counters.

Relaxation of Norms for Sugar Industry

1180. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article on sugar industry which appeared in The Economic Times of 24th July describing the Government's decision to grant licences for new capacity with diluted norms as arbitrary and politically motivated;

(b) whether it is a fact there are already 400 sugar mills in operation with another 100 mills in the pipeline, and modernisation and expansion programmes in progress, resulting in a capacity of 160 lakh tons per annum which is the targetted production capacity for 2000 AD; and

(c) if so, what are the reasons for granting new licences especially with diluted norms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) There are 396 installed sugar factories in the country as on 31-7-1990. During the Seventh Five Year Plan Period after the announcement of the policy guidelines on 2-1-1987, Letters of Intent have been issued to 93 sugar factories for setting up of new units and to 150 factories for carrying out expansion in their existing capacity. As a result of the above, the total licensed capacity would be 158.59 lakh tonnes as on 31-7-1990 as against the targetted installed pro-

duction capacity of 180.20 lakh tonnes for 2000 AD.

(c) The information is being collected.

राष्ट्रीय बीज निगम में वेतन असमानता

1891. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों को समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या इस संबंध में निगम के कर्मचारियों ने समय-समय पर असंतोष प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो समान कार्य के लिये समान वेतन न दिये जाने के क्या कारण है और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, नहीं। निगम में नियमित आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके अपने-अपने वेतन-मानों के अनुसार मजदूरी दी जाती है । इसी प्रकार, दैनिक/समेकित आधार पर काम कर रहे व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों अथवा अन्य अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा ऐसे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार निर्धारित मजदूरी से कम नहीं दी जाती है।

(ख) दैनिक/समेकित आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों ने समय-समय पर अपने को नियमित करने एवं मजदूरी बढ़ाने की मांग की है।

(ग) इस निगम की जनशक्ति इसके प्रचालन कार्यकलापों के लिये अपेक्षित जनशक्ति से अधिक है। 31 मार्च, 1990 को विभिन्न स्थानों पर दैनिक/समेकित आधार पर 632 व्यक्ति कार्य कर रहे थे । उन्हें अस्थायी तौर पर रखने का मुख्य कारण नियमित पदों का न होना है जिन पर उन्हें नियमित किया जा सके । राष्ट्रीय बीज निगम के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन राष्ट्रीय बीज परियोजना-3 की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम के तहत नियुक्त किये गये परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा है। इस निगम को पहले ही लगातार हानि हो रही है और इसे देखते हुये इस समय मांगों को पूरा करना संभव नहीं हो सकता।

Import of edible oil.

1182. SHRI S K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the quantity of edible oil imported annually in the years from 1985-86 to 1988-89;

(b) whether there is any bearing of import of edible oil on the foreign exchange strain;

(c) if so, what steps are being taken to offset this; and

(d) what steps are being taken to increase the indigenous production of oil seeds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) The quantity of edible oil imported through STC during the years 1985-86 to 1988-89 is as under:—

Financial Year	Qty. Lakh MT
1985-86	10.80
1986-87	13.07
1987-88	19.67
1988-89	10.89

(b) Yes, Sir.